

<p>(3) योजना के अंतर्गत संस्थाओं को की गई ऐसी प्रतिपूर्ति जो योजना के अंतर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार सीधे लाभार्थी की बजाए माइक्रो वित्त संस्थाओं को दी गई है।</p>										
<p>(4) योजना के अंतर्गत अपेक्षित प्रकार से आवश्यक प्रलेख पर्याप्त रूप से नहीं रखे गए थे। ऐसे मामलों की संख्या जहां रिकार्डों में हेराफेरी, उपरिलेखन (ओवरराइटिंग) और काटाकूटी की गई है।</p>										
<p>(5) लाभार्थियों को दिशानिर्देशों के अनुसरण में लाभ प्रदान नहीं किए गए थे। योजना के या तो अनुचित लाभ प्रदान किए गए अथवा लाभार्थियों को उन्हें देय उचित राशि से वंचित रखा गया।</p>										
<p>(6) योजना के अंतर्गत नामे डाले गए/दावा किए गए प्रभार/ब्याज दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थे अथवा वे वहन नहीं किए गए थे।</p>										

<p>(7) शहरी सहकारी बैंकों के संबंध में दावों की प्रतिपूर्ति की गई थी, हालांकि लाभार्थियों के खातों की संख्या के अनुसार रिकार्ड पर बुनियादी बैक-अप सामग्री नहीं थी।</p>										
<p>(8) जारी न किए गए ऋण माफी/ राहत प्रमाणपत्र</p>										
<p>(9) ऐसे मामले जहां प्रमाणपत्रों को और उधारकर्ता संस्थाओं द्वारा दिया गया डाटा को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए</p>										